भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2231
20 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारिता प्रणाली

2231. श्री हनुमान बेनीवाल:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पंजीकृत सहकारी समितियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) पंजीकृत सहकारी समितियों को दिए गए लाभों और प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में सहकारी समितियों के पंजीकरण बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) देश में सहकारी समितियों के कल्याण के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है, और
(ङ) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान देश में सहकारी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ङ): भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा प्रकाशित स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल-2018 के अनुसार देश में लगभग 8.54 लाख सहकारी समितियां हैं । सहकारी समितियों का राज्य-वार और क्षेत्रक-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर संलग्न है । सहकारिता क्षेत्र, अपने सदस्य आधारित दृष्टिकोण के साथ देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य किसी एक राज्य में सीमित होते हैं, वे संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम द्वारा शासित होते हैं जबकि ऐसी सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य किसी एक राज्य में सीमित नहीं होते हैं, वे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधनियम, 2002 और उसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों द्वारा प्रशासित होते हैं । देश में कुल 1528 बहुराज्यीय सहकारी समितियां पंजीकृत हैं । विगत तीन वर्षों में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	वर्ष	समितियां की संख्या
1.	2020	10
2.	2021	14
3.	2022 (30 नवम्बर, 2022 तक)	63
	कुल	**87**

देश में सहकारी तंत्र को सशक्त करने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित विभिन्न पहलें की गई हैं:

i. आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 29 जून, 2022 के आदेश के माध्यम से 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से अगले तीन वर्षों में 63,000 कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना को अनुमोदित किया गया । इस परियोजना में सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर में लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना शामिल है ।

ii. पैक्स के लिए आदर्श उपविधियों को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और संबंधित मंत्रालयों सहित हितधारकों के साथ गहन परामर्श के पश्चात् पैक्स द्वारा उनके संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुसार अपनाए जाने के लिए तैयार किया गया । पैक्स की इन आदर्श उपविधियों के कारण वे डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, गोदामों के निर्माण, खाद्यान्न की खरीद, उर्वरक, बीज, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग अभिकर्ता, कॉमन सेवा केन्द्र, आदि जैसे 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप कर सकेंगे ।

iii. दिनांक 1 जून, 2022 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों को गवर्मेंट इ-मार्केटिंग प्लैटफॉर्म पर बतौर 'क्रेता' पंजीकृत होने की अनुमति देने का निर्णय दिया । इससे वे देश भर में जेम पोर्टल पर पंजीकृत 40 लाख से भी अधिक विक्रेताओं से माल व सेवाओं की खरीद कर सकेंगे। इससे सहकारी समितियों को किफायती खरीद करने में सहायता मिलेगी और उनकी खरीद प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी ।

iv. सहकारी समितियों और उसके सदस्यों की आय में वृद्धि के लिए 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की कुल आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है।

v. कॉर्पोरेट के अनुरूप समान अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) दर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है ।

vi. सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडल को गति प्रदान करने के लिए सहकारी संस्थानों को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण प्रदान करने हेतु गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दिनांक 3 फरवरी, 2022 के परिपत्र के द्वारा गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTMSE) योजना में सदस्य ऋणदाता संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

vii. सरकार ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को एक बड़ी राहत देते हुए यह स्पष्ट किया कि उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) या राज्य परामर्श मूल्य (SAP), जो भी दशा हो, तक किसानों को गन्ने के उच्चतर मूल्यों का भुगतान करने पर चीनी सहकारी मिलों को अतिरिक्त आयकर नहीं चुकाना होगा ।

viii. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), जो सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और प्राथमिक/ जिला सहकारी विपणन समितियों का शेयर पूंजी आधार का संशक्तिकरण, प्रसंस्करण केन्द्रों, भंडारण सुविधाओं की स्थापना, शीत श्रृंखला की स्थापना व आधुनिकीकरण, सहकारी बैंकिंग इकाइयों की स्थापना, कृषि सेवाओं, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण में सहायता, सहकारी उद्यम सहयोग और नवाचार के लिए 'युवा सहकार', स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को कवर करने वाली 'आयुष्मान सहकार', महिला सहकारी समिति की सहायता के लिए 'नंदिनी सहकार', आदि जैसे विभिन्न कार्य करता है ।

देश में सहकारी समितियों के कल्याण के लिए दिनांक 01.04.2017 से 14.12.2022 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा स्वीकृत और जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** पर संलग्न है ।

*****

अनुबंध -1

एनसीयूआई द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय प्रोफाइल 2018 के अनुसार

	गैर-क्रेडिट समितियां																			क्रेडिट समितियां								
राज्य/केन्द्रीय शासित प्रदेश	मार्केटिंग	कंज्यूमर	डेरी	हाउसिंग	शुगर	लेबर	फिशरी/पिसिकल्चर/एक्वाकल्चर	पशुधन और मुर्गी पालन	कपड़ा/हथकरघा/स्पिंडलेज/हस्तशिल्प	कृषि-संबद्ध/कृषि-प्रसंस्करण	औद्योगिक	महिला	मल्टी-स्टेट	मल्टी-परपस	सेवा क्षेत्र	ट्राइबल/एससी-एसटी	एस सी यू	अन्य	कुल - नॉन क्रेडिट	पैक्स	पीसीएआरडीबी	यूसीबी	एम्प्लोयी थ्रिफ्ट और अन्य क्रेडिट	डीसीसीबी	एससीबी	एससीएआरडीबी	कुल क्रेडिट	कुल योग(गैर-क्रेडिट+क्रेडिट)
अंदमान और निकोबार	62	69	0	76	0	1126	112	53	0	25	115	41	0	288	0	19	1	0	1987	51		0	65		1		117	2104
आंध्र प्रदेश	14	777	3538	716	10	4520	2361	1	483	1305	0	718	18	0	1414	2	1	54466	70344	2051		48	761	13	1		2874	73218
अरुणाचल प्रदेश	2	36	7	0	0	259	11	3	23	14	3	4	1	326	1	0	1	40	731	34		0	17		1		52	783
असम	31	282	440	147	1	32	456	757	5	394	421	2341	5	246	0	80	1	850	6489	766	1	8	2980		1	1	3757	10246
बिहार	522	1875	4280	2742	0	4577	387	237	1095	1829	2723	430	18	261	187	0	1	9187	30351	8463		3	327	23	1	1	8818	39169
चंडीगढ़	1	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	225	17		0		0	1		18	243
छत्तीसगढ़	186	951	768	387	0	57	766	0	1	5812	109	287	8	534	0	0	1	144	10011	1333		12		6	1	1	1353	11364
दादरा और नागर हवेली	6	13	14	96	1	4	7	8	0	1	44	5	1	1	31	0	1	11	244	2		0	38				40	284
दमन और दियू	0	1	1	22	0	2	1	0	0	6	4	6	0	2	2	1		49	97	0		0	9				9	106
दिल्ली	0	820	0	2099	0	0	0	0	1	212	1206	0	134	170	2	0	1	279	4924	0		15	1420		1		1436	6360
गोआ	20	103	183	1	0	22	18	1	0	83	0	130	2	1934	0	0	1	895	3393	81		6	341		1		429	3822
गुजरात	2181	2014	18614	17462	31	3835	640	0	9	6746	4535	15	35	160	0	0	1	6588	62866	8484		220	5960	18	1	1	14684	77550
हरीयाना	91	23	7325	7660	15	7725	1	110	2	74	0	4	12	738	0	0	1	33	23814	711	19	7		19	1	1	758	24572
हिमाचल प्रदेश	326	374	563	93	0	103	65	0	391	29	119	17	1	116	0	261	1	340	2799	2127	20	5	439	2	1	1	2595	5394
जम्मू और कश्मीर	111	49	158	61	0	48	1	443	2	0	0	0	0	45	0	0	1	449	1368	643		4		3	1	1	652	2020
झारखण्ड	1	481	540	757	0	1923	386	58	267	425	1366	214	8	122	0	0	0	2913	9461	2345		2	2038	8	1		4394	13855

कर्नाटक	111	1344	15275	1736	38	194	636	50	1227	3941	954	1462	26	2511	250	26	1	730	30512	5679	178	264	4282	21	1	1	10426	40938
केरल	617	4646	3271	400	0	657	655	49	8	128	23	1162	20	314	327	827	1	3072	16177	1647	79	60	1284	14	1	1	3086	19263
लक्षद्वीप	11	2	0	0	0	5	6	0	7	0	15	0	0	1	15	0	0	0	62	19		0					19	81
मध्य प्रदेश	380	4977	9554	2946	1	784	2460	119	968	2093	1525	5675	26	1597	0	272	1	5701	39079	4457	35	51	3753	38	1	1	8336	47415
महाराष्ट्र	1226	1808	13948	101543	180	11269	3300	2951	1738	3456	222	442	562	350	9	1	1	366	143372	21217		502	40762	31	1	1	62514	205886
मणिपुर	24	119	562	173	0	249	416	423	6138	366	0	0	1	155	2	1	1	277	8907	223	1	3	102		1		330	9237
मेघालय	29	54	87	15	0	6	72	109	88	57	103	122	0	456	1	0	1	109	1309	179		3	63		1		246	1555
मिजोरम	7	97	115	6	0	12	58	264	216	246	60	1	0	131	0	7	1	55	1276	159		1			1		161	1437
नागालैंड	86	167	181	38	0	2	398	470	527	1324	51	0	1	3819	73	32	1	128	7298	1719		0	41		1		1761	9059
ओडिशा	1	1	5588	1	0	96	1086	2060	1325	0	117	0	19	0	0	151	1	4155	14601	2701		9		17	1	1	2729	17330
पुदुचेरी	3	37	125	1	0	27	68	0	23	0	14	7	5	62	0	0	1	23	396	53		1	80		1	1	136	532
पंजाब	85	94	6317	684	8	1720	3	0	3	85	1978	1035	23	0	0	0	1	1286	13322	3543	89	4	457	20	1	1	4115	17437
राजस्थान	491	195	12897	976	0	1020	35	0	4	1	1027	5159	72	0	0	0	1	63	21941	6411	36	37	3	29	1	1	6518	28459
सिक्किम	108	62	345	0	0	2938	8	53	1401	1	18	36	1	207	0	0	1	0	5179	176		1	107		1		285	5464
तमिलनाडु	128	1447	11302	1035	354	85	1364	0	1	52	0	1809	87	46	7	22	1	109	17849	4511	180	129	1788	23	1	1	6633	24482
तेलंगाना	10	1	1850	0	1	0	4016	1	767	1	0	0	3	0	1024	1	1	56620	64296	798		52		9	1		860	65156
त्रिपुरा	1	228	119	5	0	63	155	23	256	90	142	75	0	215	70	4	1	331	1778	268	0	1	18		1	1	289	2067
उत्तर प्रदेश	259	1058	26150	4184	0	935	1034	140	408	981	0	56	136	125	105	0	1	33	35605	8929		66	3536	50	1	1	12583	48188
उत्तराखंड	30	7	4008	1	15	10	19	0	118	55	419	161	4	0	0	0	1	0	4848	759		5		10	1		775	5623
पश्चिम बंगाल	238	2143	3831	6084	1	2648	2669	0	5	69	0	60	47	0	259	0	1	1784	19839	7405	24	43	6326	17	1	1	13817	33656
कुल	7399	26355	151956	152351	656	46953	23670	8383	17507	29901	17313	21493	1277	14932	3779	1707	32	151086	676750	97961	662	1562	76997	371	33	19	177605	854355

अनुबंध - II

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार स्वीकृति एवं जारी

01/04/2017 से 31/03/2018

रु. लाखों में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान	स्वीकृति	जारी
आंध्र प्रदेश	1,27,380.46015	91,649.62815
अरुणाचल प्रदेश	0.00000	1,479.81950
असम	4,440.15000	328.26000
बिहार	61,705.48155	6,337.80155
दिल्ली	0.00000	9.77960
आईएफ़एफ़डीसी	45.87188	94.33000
इफको	1,000.00000	1,000.00000
एनसीसीटी	1.99000	1.99000
एनएलसी फेडरेशन	3.00000	3.00000
एनएसीओएफ	0.00000	4,930.00000
गोवा	0.00000	16.33000
गुजरात	27,390.45757	27,409.71414
हरियाणा	32,355.41000	31,963.68970
हिमाचल प्रदेश	7,935.64700	3,235.93889
जम्मू और कश्मीर	41.56650	433.76875
कर्नाटक	44,745.15000	45,023.41950
केरल	1,52,689.01700	92,894.11150
मध्य प्रदेश	2,27,946.51000	2,65,939.87725
महाराष्ट्र	2,91,784.70800	2,24,577.40082
मिजोरम	0.00000	849.12800
नागालैंड	5,231.26000	1,737.45450
ओडिशा	12,149.97600	3,341.88463
पंजाब	95,000.00000	38,043.75000
राजस्थान	10,222.97800	20,393.77546
तमिलनाडु	1,706.00000	14,310.67400
उत्तर प्रदेश	2,05,900.00000	1,84,025.41900
पश्चिम बंगाल	2,068.30000	1,697.73900
छत्तीसगढ़	8,75,831.45050	8,55,145.36080
झारखंड	28.48423	162.26541
उत्तराखंड	240.52700	332.13600
अंडमान और निकोबार द्वीप	118.27200	108.41600
अन्य	560.39356	560.39356
तेलंगाना	1,01,911.07600	2,78,920.79386
कुल	**22,90,434.13694**	**21,96,958.04957**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार स्वीकृति एवं जारी

01/04/2018 से 31/03/2019

रु. लाखों में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान	स्वीकृति	जारी
आंध्र प्रदेश	1,32,756.33000	71,962.89400
अरुणाचल प्रदेश	1,619.75000	1,032.25000
असम	3,114.50400	3,563.80000
बिहार	5,636.16200	15,340.56100
नेफेड	0.64178	5.01736
आईएफ़एफ़डीसी	3,00,000.00000	3,00,000.00000
गोवा	370.16000	264.40000
गुजरात	49.83800	0.00000
हरियाणा	17,884.69500	33,840.15612
हिमाचल प्रदेश	30,250.70000	30,919.82100
कर्नाटक	9,259.70900	4,518.88274
केरल	15,506.09300	26,924.25500
मध्य प्रदेश	36,754.46000	27,361.96500
महाराष्ट्र	1,67,995.56800	1,50,675.25323
मणिपुर	1,68,063.74561	1,78,427.31653
मेघालय	35.40000	0.00000
मिजोरम	20,471.00000	5,118.00000
नागालैंड	0.00000	1,974.98200
ओडिशा	729.58000	465.28400
पंजाब	20,000.00000	10,529.41500
राजस्थान	5,30,048.62000	3,83,279.78900
तमिलनाडु	14.16000	0.00000
त्रिपुरा	419.00000	7,979.74300
उत्तर प्रदेश	1,32,540.93700	85,924.90200
पश्चिम बंगाल	87,895.85000	32,934.13000
छत्तीसगढ़	8,50,034.00000	8,00,031.01000
झारखंड	3,426.88000	82.75100
उत्तराखंड	3,01,223.26200	10,606.53400
अंडमान और निकोबार द्वीप	14,493.03300	0.00000
अन्य	554.18899	554.18899
तेलंगाना	6,69,085.10000	6,42,933.45241
कुल	**35,20,233.36738**	**28,27,250.75338**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार स्वीकृति एवं जारी
01/04/2019 से 31/03/2020

रु. लाखों में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान	स्वीकृति	जारी
आंध्र प्रदेश	42,261.35000	40,562.14700
अरुणाचल प्रदेश	312.50000	756.25000
असम	0.00000	1,433.72700
बिहार	58,582.58153	45,440.48353
नेफेड	15,000.00000	7,426.00000
आईएफ़एफ़डीसी	307.65000	305.45688
गोवा	0.00000	11.09500
गुजरात	16,886.20500	11,834.35724
हरियाणा	8,90,000.00000	6,60,857.59542
हिमाचल प्रदेश	3,661.21000	5,969.28720
कर्नाटक	16,481.08400	15,166.76700
केरल	45,073.10900	36,389.02600
मध्य प्रदेश	1,35,048.80000	1,08,169.72453
महाराष्ट्र	1,44,008.90008	1,01,506.53116
मणिपुर	957.87300	478.93600
मेघालय	20,947.50000	0.00000
मिजोरम	90.00000	0.00000
नागालैंड	0.00000	1,337.01900
ओडिशा	160.00000	374.70300
पंजाब	0.00000	13,527.70300
राजस्थान	7,14,547.19050	7,25,674.36432
तमिलनाडु	10.62000	2,123.89500
त्रिपुरा	0.00000	304.97500
उत्तर प्रदेश	1,25,646.18600	67,309.53636
पश्चिम बंगाल	1,750.00000	12,834.85000
छत्तीसगढ़	8,00,040.17455	5,50,034.72705
झारखंड	0.00000	824.93900
उत्तराखंड	0.00000	1,233.90496
अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00000	1,027.67000
अन्य	544.47226	544.47226
तेलंगाना	3,85,327.12500	3,56,882.85577
कुल	**34,17,644.53092**	**27,70,342.99868**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार स्वीकृति एवं जारी
01/04/2020 से 31/03/2021 तक

रु. लाखों में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान	स्वीकृति	जारी
आंध्र प्रदेश	58,200.00000	60,398.42200
अरुणाचल प्रदेश	0.00000	143.75000
असम	175.00000	559.34100
बिहार	2,01,100.00000	1,63,360.10300
दिल्ली	232.00000	232.00000
आईएफ़एफ़डीसी	0.00000	153.82500
गोवा	0.00000	19.23000
गुजरात	6,323.48300	5,225.06725
हरियाणा	12,52,724.95000	6,64,511.39300
हिमाचल प्रदेश	2,990.55800	3,690.42900
जम्मू और कश्मीर	150.00000	0.00000
कर्नाटक	11,773.20000	17,069.36000
केरल	20,645.35000	30,354.04975
मध्य प्रदेश	95,460.15000	20,836.27468
महाराष्ट्र	99,946.55798	1,14,559.11098
मणिपुर	15,677.31000	0.00000
मेघालय	0.00000	5,780.40500
मिजोरम	699.74000	216.01200
नागालैंड	200.00000	607.18800
ओडिशा	317.50000	80.00000
पंजाब	20,325.00000	2,276.89000
राजस्थान	30,604.00000	15,780.20200
तमिलनाडु	650.00000	2,158.15250
त्रिपुरा	0.00000	320.02500
उत्तर प्रदेश	58,136.59900	82,795.47200
पश्चिम बंगाल	0.00000	5,912.54200
छत्तीसगढ	12,00,450.00000	12,00,007.34375
झारखंड	429.49200	92.37500
उत्तराखंड	550.00000	1,722.35300
पुदुचेरी	4.11700	0.00000
अन्य	474.90354	474.90354
तेलंगाना	5,75,502.23700	73,987.54569
कुल	**36,53,742.14752**	**24,73,323.76514**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार स्वीकृति एवं जारी

01/04/2021 से 31/03/2022 तक

रु. लाखों में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान	**स्वीकृति**	**जारी**
आंध्र प्रदेश	5,89,075.00000	2,83,158.57147
अरुणाचल प्रदेश	25.00000	25.00000
असम	88.14530	356.81930
बिहार	2,50,161.20036	2,85,789.59236
दिल्ली	40.48821	34.05821
गुजरात	1,304.67065	3,740.00219
हरियाणा	7,63,731.43059	12,82,774.87959
हिमाचल प्रदेश	977.38538	1,474.15638
जम्मू और कश्मीर	100.00000	12.81600
कर्नाटक	2,411.25907	16,449.32507
केरल	26,691.85065	37,184.55265
मध्य प्रदेश	17,333.00303	47,709.92391
महाराष्ट्र	57,098.99073	68,807.28673
मणिपुर	50.00000	4.27200
मेघालय	100.00000	4.27200
मिजोरम	0.00000	106.40500
नागालैंड	100.00000	17.08800
ओडिशा	724.62627	406.31727
पंजाब	0.00000	12.81600
राजस्थान	273.36507	778.81511
सिक्किम	2.08000	0.00000
तमिलनाडु	26,393.44449	5,074.74632
त्रिपुरा	0.00000	300.00000
उत्तर प्रदेश	1,00,288.31223	25,233.04987
पश्चिम बंगाल	88.66178	4,416.04178
छत्तीसगढ	16,90,145.72754	12,40,086.64529
झारखंड	184.11233	178.86457
उत्तराखंड	7.75191	8,036.17791
चंडीगढ़	2.70687	2.70687
अन्य	712.37113	712.37113
तेलंगाना	99,011.54808	1,09,220.20294
कुल	**36,27,123.13167**	**34,22,107.77592**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार स्वीकृति एवं जारी
01/04/2022 से 14/12/2022 तक

रु. लाखों में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान	स्वीकृति	जारी
आंध्र प्रदेश	7,50,268.55000	2,73,709.12978
अरुणाचल प्रदेश	33.50000	33.50000
असम	305.36500	40.07990
बिहार	5,00,731.00000	259.58983
दिल्ली	200.00000	19.85400
आईएफ़एफ़डीसी	68.75000	0.00000
गुजरात	1,35,087.22600	837.32238
हरियाणा	6,32,568.00000	6,62,122.82469
हिमाचल प्रदेश	616.00000	567.44272
जम्मू और कश्मीर	108.00000	23.55400
कर्नाटक	2,129.07000	1,823.48325
केरल	66,174.65000	24,796.36030
मध्य प्रदेश	47,527.54250	21,200.16156
महाराष्ट्र	1,25,481.49098	21,680.87419
मणिपुर	176.60000	15.93159
मेघालय	2.10000	2.10000
मिजोरम	282.67000	184.97300
नागालैंड	3,102.32000	65.73361
ओडिशा	351.23400	47.89540
पंजाब	10,00,259.00000	35.23000
राजस्थान	40,436.26800	157.39488
सिक्किम	25.00000	1.24000
तमिलनाडु	1,181.24000	1,718.65200
त्रिपुरा	313.17000	806.39401
उत्तर प्रदेश	3,11,410.32450	4,540.93914
पश्चिम बंगाल	650.00000	1,706.44600
छत्तीसगढ	18,08,112.00000	50,106.91336
झारखंड	6,514.19000	314.05053
उत्तराखंड	438.37100	122.63800
अन्य	38.36658	38.36658
तेलंगाना	13,86,936.97500	9,00,978.68161
कुल	**68,21,528.97356**	**19,67,957.75631**